

## सिवनी और बालाघाट जिलों में कृषि आधारित उद्योगों का आर्थिक विकास में योगदान

श्रीकान्त नामदेव

शोधार्थी, गोविन्दराम सेकसरिया अर्थ-वाणिज्य, महाविद्यालय, जबलपुर

डॉ. सीमा पटारिया

सहायक प्राध्यापक, शासकीय कला महाविद्यालय, पनागर, जबलपुर

**सार** – प्रस्तुत शोध सिवनी और बालाघाट जिलों में कृषि आधारित उद्योगों के आर्थिक विकास में योगदान का विश्लेषण करता है। यह अध्ययन इन उद्योगों के महत्व, प्रभाव, और चुनौतियों पर प्रकाश डालता है।

अध्ययन से पता चलता है कि कृषि आधारित उद्योग स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो रोजगार सृजन, आय वृद्धि, और ग्रामीण विकास में योगदान देते हैं। ये उद्योग स्थानीय कृषि उत्पादों का मूल्यवर्धन करते हैं, निर्यात को बढ़ावा देते हैं, और ग्रामीण-शहरी संपर्क को मजबूत करते हैं।

हालांकि, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, वित्तीय संसाधनों की कमी, और तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता जैसी चुनौतियां इन उद्योगों के विकास में बाधा डालती हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप और समर्थन की आवश्यकता है।

### प्रस्तावना

भारत एक कृषि प्रधान देश है देश की 60 प्रतिशत जनसंख्या आज भी कृषि पर निर्भर है। वर्तमान में कृषि राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है। कृषि उत्पादन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य एवं अभिन्न हिस्सा है। भारत द्वारा विश्व में दलहन, तिलहन, चाय, आटा, मसाले, फूड प्रोडक्ट व अन्य कृषि आधारित उत्पादों का व्यापार होता है। कृषि आधारित उत्पादनों के आंतरिक एवं बाह्य व्यापार से परिवहन कर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से करदाता की आय में वृद्धि होती है। जो अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी का कार्य करती है जो हमारी आर्थिक-सामाजिक मजबूती के लिए नितांत आवश्यक है। यदि हम कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए नई तकनीक, मशीनरी, कृषि में उन्नत तकनीकों एवं नए विपणन तरीकों को अपनाकर औद्योगिक क्षेत्र में कदम रखते हैं तो हम दुनिया के प्रमुख देशों के उत्पादन स्तर से अधिक स्थान प्राप्त कर सकते हैं। कृषि संपूर्ण भारत में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक उसी प्रकार मध्यप्रदेश में भी कृषि ही सर्वप्रथम जीविका का मुख्य साधन है। यहां की लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। इसका प्रमुख कारण है कि जिले के अधिकतर लोग ग्रामीण अंचलों में निवास करते हैं। जिनका संबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से ही होता है। जिसमें कृषि आधारित उद्योग भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहन करते हैं सिवनी एवं बालाघाट जिले अधिकतम भाग पहाड़ी है जिसके कारण कृषि हेतु सभी जगह की भूमि एक जैसी नहीं है। यहां धरातलीय विषमता, मानसून पर निर्भरता, अविकसित तकनीक, जनसंख्या में ज्यादा जागरूकता का अभाव, शिक्षा तकनीकी का अभाव, उद्यमियों का अभाव, पूंजीपतियों की कमी, उद्देश्य अभाव,

यातायात का अभाव, बड़ी कृषि क्षेत्र का अभाव के कारण इस क्षेत्र में वांछित सफलता के लिए तत्पर है।

### कृषि आधारित उद्योगों का योगदान

विकासशील राष्ट्रों की आर्थिक नीतियों ने हमेशा न केवल उत्पाद और उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से, बल्कि प्रसंस्करण और विनिर्माण के माध्यम से कृषि उत्पादों में प्रणालीगत मूल्य-संवर्धन द्वारा किसानों की आय बढ़ाने की वकालत की है। भारत की विशाल जनसंख्या अभी भी कृषि और सम्बद्ध गतिविधियों में लगी हुई है। भारतीय किसान काफी हद तक असंगठित हैं। वे अपने विपणन योग्य अधिशेष के समायोजन के लिए बाहरी एजेंसियों पर निर्भर रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पूंजीगत सम्पत्ति की कमी के कारण उन्हें बिचौलियों/कमीशन एजेंटों को अपनी उपज बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। प्राथमिक कृषि उत्पादन से कम आय और प्रसंस्करण तथा कृषि-मूल्य श्रृंखला में निवेश की कमी के कारण कृषि के मुनाफे में तेजी से कमी आई है एवं कृषि कार्य अब गम्भीर दवाब में आ गया है।

केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के वार्षिक सर्वेक्षण में रिपोर्ट की गई संगठित विनिर्माण इकाइयों के औद्योगिक आंकड़े बताते हैं कि 2017-18 में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा कारखानों की संख्या कम थी। हालांकि, उनके कुल उत्पादन और क्षेत्र में शुद्ध वर्धित मूल्य के सम्बन्ध में समानता थी। इससे पता चलता है कि अधिक ग्रामीण औद्योगिक इकाइयों की स्थापना ग्रामीण अधिशेष श्रम को न केवल रोजगार प्रदान करने में अहम भूमिका निभाएगी परन्तु, कुल औद्योगिक उत्पादन और मूल्यवर्धन में भी बड़े पैमाने पर योगदान देंगी।

### मध्यप्रदेश का परिचय

मध्यप्रदेश भारत के केन्द्र में स्थित होने के कारण ही मध्यप्रदेश कहलाता है। भू-वैज्ञानिक दृष्टि से यह भारत का प्राचीनतम भाग माना जाता है। हिमालय से भी पुराना यह भू-खण्ड किसी समय उस संरचना का हिस्सा था, जिसे गोण्डवाना लैण्ड कहा गया।<sup>1</sup>

स्वाधीनता के बाद देशी रियासतों एवं छोटे-छोटे राज्यों का भारत में विलय करके भारत गणराज्य बनाया गया। देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए तथा देश के सभी क्षेत्रों का बहुमुखी विकास करने के उद्देश्य से राज्यों का पुर्नगठन 1 नवंबर 1956 को हुआ, जिसके परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश राज्य अस्तित्व में आया।

जब मध्यप्रदेश राज्य की स्थापना की गई थी, तब मध्यप्रदेश में 43 जिले व 12 संभाग थे, परन्तु बाद में क्रमशः 26 जनवरी 1972 व 25 मई 1998 को क्रमशः 2 व 10 जिले बनाए गए।

31 अक्टूबर 2000 को मध्यप्रदेश राज्य का विभाजन कर दिया गया और मध्यप्रदेश से 18 जिलों को पृथक कर 1 नवंबर 2000 से छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की गई। जिससे इस राज्य का क्षेत्रफल घटकर 3.08 लाख वर्ग कि.मी. ही रह गया।

<sup>1</sup>परमार, जबर सिंह ; कुमार, संजय : "मध्यप्रदेश विस्तार में", अरिहन्त पब्लिकेशन्स (इण्डिया) लिमिटेड ISBN 978-93-5176-505-9, पृष्ठ- 9

### सिवनी जिले का परिचय

सिवनी जिला मुख्य रूप से भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में आदिवासी आबादी का एक जिला है। सिवनी जिला मध्य भारत में मध्य प्रदेश राज्य के जिलों में से एक है। सिवनी शहर सिवनी जिले का मुख्यालय है। 2001 की जनगणना के अनुसार, जिले की जनसंख्या<sup>2</sup> 1,166,608 थी, जिसमें से 1045921 ग्रामीण आबादी और 120687 शहरी आबादी है। अनुसूचित जनजाति की आबादी 429104 है। सिवनी जिला सतपुड़ा टेबललैंड का एक हिस्सा है, जिसमें वैनगंगा के हेडवाटर शामिल हैं और बड़े पैमाने पर जंगल से आच्छादित है।

सिवनी जिले का गठन 1 नवम्बर 1956 में प्राथमिक रूप से जनजातीय बहुल जिले के रूप में किया गया। सिवनी जिले का नाम सेओना नामक वृक्ष के नाम पर किया गया। यह वृक्ष इस जिले में बहुतायत में पाया जाता है। इस वृक्ष का उपयोग ढोलक बनाने में किया जाता है। यह जिला सतपुड़ा पर्वत के उत्तर-दक्षिण में स्थित हैं। यह जिला इमारती लकड़ी का मुख्य स्रोत है। सागौन इस जिले में मुख्य रूप से पाया जाता है। सिवनी जिला मुख्यालय नागपुर-वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7 और जबलपुर नागपुर के बीच स्थित है। जिले का कुल क्षेत्रफल 8758 वर्ग कि.मी. है। ओर कुल ग्रामपंचायत 645 है। कुल ग्राम 1,599 है। 1 नगर पालिका सिवनी है नगर पंचायत 2 है लखनादौन, बरघाट। एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध- 'संजय सरोवर बांध' छपारा (भीमगढ़, सिवनी) में बैनगंगा नदी पर बना है।

### बालाघाट जिले का परिचय

बालाघाट जिला भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला है। इस जिले का मुख्यालय बालाघाट में स्थित है। यह मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व हिस्से में स्थित है। इस जिले के उत्तर पूर्व से पूर्व तक छत्तीसगढ़, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक महाराष्ट्र, पश्चिम में सिओनी जिला तथा उत्तर में मंडला जिला स्थित है।

बालाघाट जिला भारत के राज्यों में एकदम मध्य में स्थित मध्य प्रदेश राज्य में है, बालाघाट जिला मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में है, इसका उत्तर पूर्व से पूर्व तक का भाग छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं से और दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक का भाग महाराष्ट्र राज्य की सीमाओं से मिलता है, बालाघाट 21°8' उत्तर 80°18' पूर्व के बीच स्थित है, बालाघाट की समुद्रतल से ऊंचाई 288 मीटर है, बालाघाट भोपाल से 438 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर है और भारत की राजधानी दिल्ली से 1042 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर है।

### सिवनी एवं बालाघाट जिले में कृषि आधारित जनसंख्या

जिले के ग्रामीणजनों की घरेलू निर्भरता कृषि में होने के कारण कृषि विभाग, जिले का एक महत्वपूर्ण विभाग है। विभागीय संरचना जिला स्तर कार्यालय उपसंचालक कृषि हैं, जिसमें

<sup>2</sup> जिला सांख्यिकी रिपोर्ट, 2011, सिवनी जिला, मध्य प्रदेश, जिला सांख्यिकी कार्यालय, सिवनी।

उपसंचालक कृषि साथ ही पांच सहायक संचालक कृषि पदस्त हैं, जिले में दो अनुविभागीय स्तर के कार्यालय साथ ही दो सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय सिवनी एवं लखनादौन हैं। अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय सिवनी के अन्तर्गत चार वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय सिवनी, कुरई, बरघाट, केवलारी एवं अनुविभागीय अधिकारी लखनादौन के अन्तर्गत वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय छपारा, लखनादौन, घसौर, धनोरा आते हैं, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालयों में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के अधीनस्थ कृषि विकास अधिकारी एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी पदस्त हैं। कृषि विभाग सिवनी में एक प्रथम श्रेणी अधिकारी एवं नो द्वितीय श्रेणी अधिकारी कार्यरत है जिले में कार्यरत तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 117 व 12 है।<sup>3</sup>

आत्मा तथा बायफ कन्वर्जंस के मार्गदर्शन में विगत वर्षों में किए गए लगातार प्रयासों के फलस्वरूप घसौर विकासखंड (सिवनी के एक आदिवासी और दूरस्थ ब्लॉक) के ग्राम दुरजनपुर, बरेला, गोरखपुर, अतरिया, विनेकी कला, पनारझिर, बम्होड़ी, धोबीसरा गांव बगदरी में आम, आंवला, काजू और यूकेलिप्टस का वृक्षारोपण किया गया है। इन प्रयोगों से प्रभावित होकर कृषकों का फल उत्पादन की ओर रुझान बढ़ रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अंतर्गत धान का श्री पद्धति से रोपा लगाया जा रहा है। कृषक कृषि विकास योजना अंतर्गत कृषकों को रसायन मुक्त खेती के लिए प्रेरित किया जाता है।<sup>4</sup>

मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित सिवनी जिला अपनी कृषि गतिविधियों के लिए जाना जाता है और राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिले में कृषि से जुड़ी एक बड़ी आबादी है, जिसमें किसान, खेतिहर मजदूर और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े लोग शामिल हैं। इस निबंध का उद्देश्य सिवनी जिले की कृषि-आधारित आबादी का एक सिंहावलोकन प्रदान करना है, जिसमें खेती की जाने वाली प्रमुख फसलों, खेती के तरीकों और क्षेत्र में कृषि के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है।

सिवनी जिले में कृषि आधारित आबादी में कुल आबादी का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। उपजाऊ मिट्टी और अनुकूल जलवायु परिस्थितियों के साथ, कृषि जिले में बड़ी संख्या में लोगों के लिए प्राथमिक व्यवसाय और आजीविका का स्रोत बन गया है। कृषि में लगी आबादी को उन किसानों में वर्गीकृत किया जा सकता है जिनके पास जमीन है और वे फसलें उगाते हैं, खेतिहर मजदूर जो इन खेतों पर काम करते हैं, और ऐसे व्यक्ति जो पशुधन पालन, मत्स्य पालन और वानिकी जैसी सहायक गतिविधियों में शामिल हैं।

## शोध साहित्य का पुनारवलोकन

विभिन्न शोधकर्ताओं द्वारा किए गए पिछले शोध कार्यों की समीक्षा से अनुसंधानकर्ता को न केवल उचित दिशा में अनुसंधान कार्य की योजना बनाने और व्यवस्थित करने में मदद मिल सकती है बल्कि अतीत में सुधार करने का अवसर भी मिलता है। यह शोध कार्यकर्ता के लिए अनुसंधान की समस्या की रूपरेखा तैयार करने, उद्देश्यों को तैयार करने, कार्यप्रणाली का चयन करने और प्रयासों के आवश्यक दोहराव से बचने के लिए भी उपयोगी है, यह विषय के बारे में एक अंतर्दृष्टि और एकीकरण की भावना पैदा करके जांच

<sup>3</sup> भारत की जनगणना [www.censusindia.gov.in](http://www.censusindia.gov.in) पर

<sup>4</sup> मध्य प्रदेश में कृषि विभाग, आप उनकी आधिकारिक वेबसाइट [www.mpkrishi.mp.gov.in](http://www.mpkrishi.mp.gov.in) पर जा सकते हैं।

के विषय के बारे में एक सामान्य अभिविन्यास भी प्रदान करता है। शोधकर्ता मौजूदा अध्ययनों और विषय वस्तु पर जांच के क्षितिज को बनाने और सुधारने में सक्षम होगा। समीक्षा पहले के अध्ययनों में दी गई अवधारणाओं और बयानों को नकारने में और साथ ही वर्तमान अध्ययन का समर्थन करने में भी मदद कर सकती है।

**बालासुब्रमण्यम (1960)<sup>5</sup>** ने अपने लेख "भारत में कृषि प्रक्रिया की भूमिका" में भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि उपज के प्रसंस्करण की भूमिका का मूल्यांकन किया है। वह पाता है कि प्रसंस्करण कृषि उत्पादों के विपणन में सुधार करता है और विपणन लागत और मार्जिन को कम करता है, जिससे उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की गई कीमत में किसानों का हिस्सा बढ़ जाता है। लेखक का कहना है कि खाद्य पदार्थों का प्रसंस्करण उत्पादक की कीमत और उपभोक्ता की कीमत के बीच के अंतर को कम कर देता है और उत्पादों को साल भर उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा, कीमतों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव को भी कम किया जा सकता है।

**ऑस्टिन (1981)<sup>6</sup>** ने कृषि आधारित उद्योगों को तीन चरणों में वर्गीकृत किया। उसके लिए प्रसंस्करण की डिग्री सीधे पूंजी निवेश, तकनीकी और प्रबंधकीय आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। उन्होंने पाया कि कृषि आधारित उद्योगों में कच्चा माल जो मौसमी, खराब होने और परिवर्तनशीलता की विशेषता है, प्रमुख लागत घटक का गठन करता है।

**कॉनर एवं अन्य (1985)<sup>7</sup>** ने कहा कि स्थानीय पहलू, इकाइयों की परिपक्वता और उद्यमी का व्यक्तित्व आउटपुट के साथ-साथ उद्यमी के प्रदर्शन स्तर को बढ़ाता है। अवस्थिति कारक में परिवहन अवसंरचना, बाजार से दूरी और व्यावसायिक वातावरण, कच्चे माल की पर्याप्तता आदि शामिल हैं।

**अहलूवालिया आर रंगराजन (1986)<sup>8</sup>** ने तर्क दिया कि कृषि पर भारतीय उद्योगों की निर्भरता बहुत मजबूत थी और कृषि आधारित उद्योग के विकास से आगे के लिंकेज के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि करके कृषि क्षेत्र का विकास होगा और फसल कटाई के बाद के नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी।

**मोहंती (1995)<sup>9</sup>** ने उल्लेख किया कि कृषि-प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना से इलाके में फसल पैटर्न के साथ-साथ कृषि रोजगार में भी बदलाव आता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस उद्योग से संबंधित फसलों को पारंपरिक फसलों की जगह नए रूप में पेश किया जाएगा। तीन चयनित कृषि-उद्योगों (चीनी, जूट और तेल) के अपने अनुभवजन्य अध्ययन में पाया गया कि अध्ययन के तहत उड़ीसा के छह गांवों के फसल पैटर्न में परिवर्तन हुए और इसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त रोजगार का सृजन हुआ। इन उद्योगों में, चीनी मिल का फसल पैटर्न बदलने पर जबरदस्त प्रभाव है।

### कृषि आधारित उद्योगों के श्रमिकों की घरेलू आय में परिवर्तन

<sup>5</sup> बालासुब्रमण्यम, एम, भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि उपज के प्रसंस्करण की भूमिका, इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमी, वॉल्यूम 15, नंबर 1, 1960।

<sup>6</sup> ऑस्टिन, ई. कृषि उद्योग: विनिर्माण के स्थान सिद्धांत का एक उपेक्षित पहलू, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी प्रेस पृ. 7-11, 1981।

<sup>7</sup> कॉनर, जे. एट. अल., खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को आकार देने वाली आर्थिक ताकतें, अमेरिकन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, वॉल्यूम. 67, पृ. 1136-1142, 1985।

<sup>8</sup> अहलूवालिया, आई.जे. और रंगराजन, सी., कृषि और उद्योग: संबंधों का एक अध्ययन- भारतीय अनुभव, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संघ, पृ. 219-250, 1986।

<sup>9</sup> मोहंती, एन., ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर कृषि आधारित उद्योगों का प्रभाव, राधा प्रकाशन, नई दिल्ली, 1995।

वर्तमान अध्याय के इस भाग में, 2016–17 और 2019–20 की अध्ययन अवधि के बीच, घरेलू कृषि आधारित औद्योगिक श्रमिकों की कार्यशील जनसंख्या की प्रति व्यक्ति आय पर प्रकाश डालना प्रस्तावित है।

### गरा लालबरा –किसान को आय में परिवर्तन

नीचे दी गई सारणी संख्या 1 2015–16 और 2019–20 के बीच गरा गाँव में घरेलू आय में परिवर्तन का एक संक्षिप्त झलक देती है। कृषकों के घरों के परिणाम प्रारंभिक और अंतिम प्रति वर्ष अलग-अलग पैदावार और संबंधित वर्ष में फसलों की कीमत के कारण भिन्न होते हैं।

#### तालिका संख्या 1

#### गरा गाँव में कृषकों की घरेलू आय में परिवर्तन

क्र.	एकड़ में भूमिजोत का आकार	घरों की संख्या	प्रति एकड़ खेती की औसतन एकड़ भूमि	2016–17 में प्रति घर औसत आय	2019–20 में प्रति हाउस होल्ड औसत आय	प्रति घर आय में वृद्धि / कमी	प्रतिशत
1	5 से कम	63	2.5	16250 (6.5)	36250 (14.5)	20,000	123.08
2	5–10	03	5.2	31200 (6)	72800 (14)	41600	133.33
3	10–15	—	—	—	—	—	—
4	15–20	01	16.0	96000 (6.00)	222400 (13.9)	126400	131.67
5	20–25	01	21.5	150500 (7)	318200 (14.8)	111.43	167.700
6	25–30	—	—	—	—	—	—
	संपूर्ण	68	—	—	—	—	—

स्रोत: आंकड़े व्यक्तिगत सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्र किया गया।

तालिका में 2016–17 और 2019–20 के बीच गरा गाँव के कृषकों की घरेलू आय के रुझान को दर्शाता है। यह तालिका से काफी स्पष्ट है कि 2016–17 और 2019–20 के बीच की अवधि के दौरान प्रति घर के औसत आय में लगभग सभी आकार की भूमि में काफी वृद्धि हुई है। 5 से 10 एकड़ की भूमिजोत ने प्रति परिवार औसत आय में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की। जिसके बाद 15 से 20 एकड़ में घर है। भूमि के तीसरे क्रम में 20 से 25 एकड़ भूमि वाले घर थे, और प्रति परिवार औसत आय में सबसे कम वृद्धि दर्ज की

गई। फिर भी, जिसे सबसे कम कहा जाता है। वह इस शब्द के अर्थों में सबसे कम नहीं है क्योंकि कृषकों के छोटे या बड़े घरों के सभी घरों की आय में प्रति घर औसत आय में शानदार वृद्धि दर्ज की गई। वृद्धि 133 थी। 5 से 10 एकड़ भूमि वाले परिवारों के लिए 33 प्रतिशत और 131.67 प्रतिशत, 123.08 प्रतिशत और 111.43 प्रतिशत परिवारों के लिए 15 से 20 एकड़ कम और फिर 5 एकड़ और 20 से 25 एकड़ भूमि है। इसलिए, हम यह कह सकते हैं कि सभी श्रेणियों के पंजीकृत घरों में बाहरी आय बढ़ जाती है, जिससे आस-पास की धान मिलों पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है, जिससे धान की खेती करने वाले परिवारों को बहुत अधिक कीमत मिलती है।

### पलारी-कृषकों की आय में परिवर्तन

2016-17 और 2019-20 के बीच पलारी गाँव में कृषकों की घरेलू आय में परिवर्तन तालिका 6.2 से देखा जा सकता है

#### तालिका संख्या 2

#### पलारी गाँव में कृषकों की घरेलू आय में परिवर्तन

क्र.	एकड़ में भूमिजोत का आकार	घरों की संख्या	प्रति एकड़ खेती की औसतन एकड़ भूमि	2016-17 में प्रति घर औसत आय	2019-20 में प्रति हाउस होल्ड औसत आय	प्रति घर आय में वृद्धि/कमी	प्रतिशत
1	5 से कम	40	02	11000 (5.5)	24600 (12.3)	13600	123.64
2	5-10	06	5.32	31388 (5.9)	66500 (12.5)	35112	111.86
3	10-15	03	11.6	58000 (5)	139200 (12)	81200	140
4	15-20	02	16.8	100800 (6)	216720 (12.9)	115920	115
5	20-25	—	—	—	—	—	—
6	25-30	—	—	—	—	—	—
	संपूर्ण	57	—	—	—	—	—

स्रोत: आंकड़े व्यक्तिगत सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्र किया गया।

तालिका में दर्शाया गया है कि सभी घरों में अलग-अलग एकड़ जमीन है। जिसमें वर्ष 2019-20 के प्रारंभिक वर्ष 2016-17 में प्रति घर औसत आय में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। इस गाँव में 10 से 15 एकड़ भूमि वाले परिवारों की आय में वर्ष 2016-17 में वर्ष

2019–20 में 140 प्रतिशत की उच्चतम वृद्धि दर्ज की गई, जिसके बाद 123.04 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 5 एकड़ से कम भूमि वाले परिवार, अगले क्रम में 15 से 20 एकड़ भूमि वाले परिवारों और 5 से 10 एकड़ भूमि वाले घरों में क्रमशः 115 प्रतिशत और 111.88 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई।

### कटंगी कृषकों की आय में परिवर्तन

तालिका में कटंगी गाँव में कृषकों के घरेलू आय में परिवर्तन को दर्शाया गया है।

#### तालिका संख्या 3

#### कटंगी गाँव में कृषकों की घरेलू आय में परिवर्तन

क्र.	एकड़ में भूमिजोत का आकार	घरों की संख्या	प्रति एकड़ खेती की औसतन एकड़ भूमि	2016–17 में प्रति घर औसत आय	2019–20 में प्रति हाउस होल्ड औसत आय	प्रति घर आय में वृद्धि/कमी	प्रतिशत
1	5 से कम	33	2.3	15640 (6.8)	24610 (10.7)	8970	57.35
2	5–10	02	6.9	48960 (7.1)	72470 (10.5)	23460	47.89
3	10–15	—	—	—	—	—	—
4	15–20	01	17.1	124830 (7.3)	162450 (19.5)	37620	30.14
5	20–25	02	22.2	166500 (7.5)	244200 (1.1)	77700	46.67
6	25–30	01	25.9	178710 (6.9)	284900 (1.1)	106090	69.42
	संपूर्ण	39	—	—	—	—	—

स्रोत: आंकड़े व्यक्तिगत सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्र किया गया।

### कटंगी में कृषकों की घरेलू आय में परिवर्तन

जैसा कि तालिका से देखा जा सकता है कि विभिन्न प्रकार के भूमिजोत वाले घरों की औसत आय में संतोषजनक वृद्धि दर्ज की गई, जो पास की कृषि निर्माण इकाइयों के कारण हैं, इससे इन इकाइयों में नौकरियों के कारण कृषकों की आय में वृद्धि हुई है। 25–30 एकड़ भूमि की भूमि वाले परिवारों ने प्रति परिवार औसत आय में 59.12 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की। 5 एकड़ से कम भूमि वाले परिवारों ने 57.35 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की। 15 से



20 एकड़ भूमि वाले परिवारों ने 30रु14 प्रतिशत की सबसे कम वृद्धि दर्ज की और 5–25 एकड़ भूमि वाले परिवारों और 20–25 एकड़ भूमि वाले परिवारों ने क्रमशः 47.89 प्रतिशत और 46.67 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

### निष्कर्ष

आजादी के बाद से मध्यप्रदेश ने उल्लेखनीय विकास हासिल किया है। यह भारत के उन कुछ राज्यों में से एक है जहां तीव्र कृषि विकास ने तेजी से औद्योगीकरण को प्रेरित किया है। यह विकास और समृद्धि मुख्य रूप से 1960 के दशक के दौरान मध्यप्रदेश द्वारा कृषि में नवीनतम तकनीक को अपनाने का परिणाम है और कुछ ही वर्षों में राज्य भारत में हरित क्रांति का प्रतीक बन गया।

स्थानीय रूप से उपलब्ध कृषि कच्चे माल, जैसे कपास, धान, दूध, फल और सब्जियां और पोल्ट्री मध्यप्रदेश में प्रमुख कृषि-आधारित उद्योगों जैसे सूती वस्त्र, आधुनिक चावल मिलों और डेयरी उद्योग सहित खाद्य प्रसंस्करण के लिए एक समृद्ध इनपुट आधार प्रदान करते हैं। कृषि क्षेत्र में आय के अवसरों को बढ़ाने के अलावा, ये संबंध कृषि विविधीकरण को प्रोत्साहित करते हैं और भूमि और जल संसाधनों के अधिक संतुलित उपयोग को बढ़ावा देते हैं।

### संदर्भ ग्रंथ सूची

1. अग्रवाल, ए.के. (1991), उत्तर पूर्व भारत में कृषि-आधारित उद्योगों के माध्यम से ग्रामीण विकास – एक परिप्रेक्ष्य, खादी ग्रामोद्योग, वॉल्यूम 37, क्रमांक 3।
2. अहमद, इकबाल एस. (1978), आंध्र प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों का एक अध्ययन, दक्षिणी अर्थशास्त्री, वॉल्यूम 17, क्रमांक 14।
3. अर्पुथराज, सी. (1982), भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था, मैकमिलन इंडिया।
4. आर्य, अनीता और एस. पी. कश्यप (1997), भारत में कृषि-प्रसंस्करण उद्योगों की समस्याएं और संभावनाएं, पीएसई आर्थिक विश्लेषक, खंड 17 और 18, संख्या 1 और 2।
5. बालासुब्रमण्यम, एम (1960) भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि उपज के प्रसंस्करण की भूमिका, इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, खंड 15, नंबर 1।
6. बागलकोटी, एस.टी. (1996), ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि गतिविधियाँ: कृषि-प्रसंस्करण के लिए एक मामला, कृषि विकास में अध्ययन में, (संस्करण), एम.वी. गौड़ा और सुशीला सुब्रह्मण्य, दीप और दीप प्रकाशन, दिल्ली।
7. बघेल, लाल मृगेंद्र और नीलकंठ, जी. पेंडसे (1996), मध्य प्रदेश राज्य में औद्योगिक विकास में कृषि आधारित उद्योगों की भूमिका, खादी ग्रामोद्योग, वॉल्यूम 42, क्रमांक 10।
8. बंदरला, अमरनाथ (1991), कृषि-आधारित उद्योगों की समस्याएं, दक्षिणी अर्थशास्त्री, खंड 30, संख्या 9।
9. बायिनेनी, श्रीनिवासुलु और रमेश बाबू वूका (2004), भारत में कृषि-आधारित उद्योगों का विकास, द आईयूपी जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, वॉल्यूम 2, अंक 3।
10. भल्ला, जी.एस. (1995), एग्रीकल्चरल ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन पंजाब, इन एग्रीकल्चर ऑन द रोड टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, (संस्करण) जॉन मेलोर, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी प्रेस, बाल्टीमोर और लंदन।